



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1944 (श10)

(सं0 पटना 642) पटना, बुधवार, 31 अगस्त 2022

सं० 2/नि0था0-11-08/2014-सा0प्र0/9529  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

13 जून 2022

श्री अभिराम त्रिवेदी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 964/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, वैशाली-सह-अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक 84/गो0-1 दिनांक 02.05.2014 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र गठित किया गया।

श्री त्रिवेदी के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोप निम्नलिखित हैं :-

“आर्थिक अपराध इकाई-1, बिहार, पटना को गोपनीय स्रोतों से जानकारी मिली थी कि श्री अभिराम त्रिवेदी, वरीय उप समाहर्ता ने अपने सेवाकाल में अवैध कमाई कर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की है। इसी सूचना के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई-1 द्वारा श्री अभिराम त्रिवेदी, वरीय उप समाहर्ता के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना कांड सं0 25/2014 दिनांक 29.04.2014, धारा-13(2) सहपठित धारा-13(1)(E) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत पंजीकृत किया गया है। विशेष निगरानी इकाई द्वारा इनके विरुद्ध आय के ज्ञात स्रोतों से प्राप्त कुल आय रु0 49,65,000/- से रु0 1,03,50,000/- अधिक की परिसम्पत्तियाँ अर्जित करने की प्राथमिक सूचना प्रतिवेदित है।

निगरानी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति के उद्भेदन के आलोक में श्री त्रिवेदी का आचरण सरकारी सेवक के आचरण के अनुकूल नहीं है और इनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। इनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम 3(1)(i)(ii)(iii) के प्रतिकूल है।

श्री त्रिवेदी के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 9478 दिनांक 11.07.2014 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण किया गया। साथ ही विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9479 दिनांक 11.07.2014 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया। श्री त्रिवेदी का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1865 दिनांक 04.02.2015 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 12467 दिनांक 22.10.2021 द्वारा लिखित अभिकथन/बचाव अभ्यावेदन की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में श्री त्रिवेदी द्वारा बचाव अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री त्रिवेदी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचिका में उपलब्ध अभिलेख एवं लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में श्री त्रिवेदी को बिहार आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री त्रिवेदी के बचाव अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4820 दिनांक 29.03.2022 द्वारा (i) संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धि पर रोक एवं (ii) देय प्रोन्नति की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक के लिए प्रोन्नति पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया।

उक्त दंडादेश पर पुनर्विचार हेतु श्री त्रिवेदी के पत्रांक-शून्य दिनांक 21.04.2022 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनका कहना है कि :-

विशेष निगरानी इकाई द्वारा कोई सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं दिया गया तथा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। निगरानी द्वारा कोई उद्भेदन या कार्रवाई नहीं की गई। स्पष्टीकरण के लिए इन्हें वांछित कागजात नहीं दिया गया, जो नियमावली के नियम-17(4) के तहत देय था तथा स्पष्टीकरण का मौका नहीं देते हुए नियमावली के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। सचिव श्रम संसाधन विभाग सह अपर जाँच आयुक्त का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 667 दिनांक 08.02.2016 पूर्ण रूपेण नियम संगत एवं विधि संगत है। विभागीय उपस्थापन पदाधिकारी का अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया या मंतव्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे आरोप प्रमाणित हो सके। बचाव पक्ष के अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य एवं स्पष्टीकरण का खण्डन विभाग द्वारा नहीं किया जा सका। बार-बार प्रमाणित हो चुका है कि दिनांक 09.09.2016 तक आर्थिक अपराध इकाई को वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं थी, जो मान0 उच्च न्यायालय में C.W.J.C.No.7549/15 के आदेश एवं पुलिस अधीक्षक के पत्रांक 85, दिनांक 24.06.2016 से स्पष्ट है, स्पष्टतः दिनांक 02.03.2016 का प्रतिवेदन असत्य एवं निराधार है।

विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक कार्यवाही अलग-अलग है, लेकिन पत्रांक 1201, दिनांक 02.03.2016 के प्रतिवेदन आधारित अग्रेतर जाँच का निर्णय विरोधाभासी है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा पुनः उपस्थापन पदाधिकारी एवं आर्थिक अपराध इकाई (अभियोजन पक्ष) को पर्याप्त मौका दिया गया, लेकिन आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका। पुलिस पदाधिकारी प्रतिपरीक्षण/परीक्षण में कोई ठोस साक्ष्य नहीं दे पाए।

मान0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.9.2016 को पारित न्यायादेश का अवहेलना करते हुए 06 सप्ताह में विभागीय कार्यवाही का निर्णय नहीं किया गया। विधि विरुद्ध एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही तीसरी बार प्रारंभ की गई, जो साक्ष्यहीन एवं आधारहीन है। बचाव बयान में स्पष्ट किया गया है कि मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित व्यवस्था में तीसरी बार जाँच को सिर्फ प्रताड़ना माना गया है। इनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही स्थगित है, किस आधार पर आरोप को संपुष्ट किया जा सकता है, जिसे मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी स्थगित की जा चुकी है। आरोप, घोषणा आदि पर कोई भी निर्णय मान0 सर्वोच्च न्यायालय में स्थगित एवं विचाराधीन है, तत्काल उनके आधार पर कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जा सकता है।

संचालन पदाधिकारी के संपूर्ण मंतव्य पर विचार करने के उपरांत निष्कर्ष पर निर्णय दिया जा सकता है, किसी अंश मात्र से नहीं। संचालन पदाधिकारी का कथन विधिसंगत है जो अर्धन्यायिक न्यायालय द्वारा अभिकथित है जिसका खण्डन अभिलेख में उपस्थित साक्ष्य के आधार पर नहीं किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई एक गवाह मात्र है जिसके साक्ष्य एवं प्रतिवेदन का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण जाँच आयुक्त न्यायालय द्वारा किया गया तथा आरोप असत्य एवं अप्रमाणित पाया गया। एक तरफ विभागीय कार्यवाही को स्वतंत्र मानकर निर्णय लिया जाता है, दूसरी तरफ न्यायिक कार्यवाही से संबद्ध नहीं किया जा सकता है और अगर संबद्ध किया जाए तो न्यायिक कार्यवाही के फलाफल की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। प्रपत्र 'क' में या आर्थिक अपराध इकाई के पत्रांक 1201 दिनांक 02.03.2016 में कहीं भी अंकित नहीं है कि अनुसंधान में आरोपी द्वारा अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय किया गया है। यह पूर्णरूपेण असत्य तथ्यों पर आधारित असहमति का बिन्दु है।

आरोप सं0-2 में असहमति का बिन्दु आरोप सं0-01 से विरोधाभासी है। असहमति के बिन्दु में परिजनों द्वारा क्रय-विक्रय वर्णित है जबकि प्रथम आरोप के प्रतिवेदन से असहमति में स्वयं आरोपी द्वारा क्रय-विक्रय वर्णित है। विस्तृत रूप से सम्यक् जाँचोपरांत प्रमाणित है कि वर्णित संपत्ति से आरोपी को कोई लेना-देना नहीं है तथा आरोप निराधार एवं अप्रमाणित है। बचाव-बयान में एवं द्वितीय कारण पृष्ठ में स्पष्ट किया जा चुका है तथा विभाग द्वारा खण्डन नहीं किया जा सका।

विभाग द्वारा किया गया समीक्षा असत्य तथ्यों पर आधारित है। इनके द्वारा कभी भी या कहीं भी कहा नहीं गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2019 के न्यायादेश में विभागीय

कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 1257/2017, माननीय न्यायालय में इनके द्वारा दायर नहीं किया गया है बल्कि CR.WJC दायर किया गया। यह कथन पूर्णतः असत्य एवं निराधार है। इनके द्वारा गलत तथ्य उपस्थापित नहीं किया गया। बार-बार कहा गया है कि न्यायिक कार्यवाही पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा T.P. CR.No-620/2019 में दिनांक 06.12.2019 को रोक लगायी गयी है। यह आदेश क्रिमिनल रीट से संबंधित है, विभागीय कार्यवाही (सिविल रिट) से नहीं। इस आदेश के विश्लेषण में भी खुद विभाग द्वारा पृष्ठ सं0-6 के कंडिका (i) एवं (ii) पर स्वीकार किया गया है।

इनके द्वारा यह नहीं गया कि आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध नहीं कराया गया या परीक्षण/प्रतिपरीक्षण का मौका नहीं किया गया। यह कथन पूर्णतः असत्य एवं भ्रामक है। न्यायालय में विचाराधीन आरोप-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया तथा परीक्षा नहीं कराया गया। पुनः दोहराया जाता है कि विभागीय जाँच मंतव्य विधिवत् संपूर्ण जाँच पर आधारित है। इसी कंडिका में विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है तथा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद प्रश्न उठाना न्यायसंगत नहीं है।

न्यायिक कार्यवाही एवं विभागीय कार्यवाही को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के तहत स्वतंत्र रूप से चलाई जा सकती है, बशर्ते आरोप एवं साक्ष्य समान नहीं हो तथा न्यायालय में बचाव प्रभावित नहीं हो तथा बचाव की गोपनीयता भंग नहीं हो, जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। राजस्थान राज्य बनाम बी0के0 मीणा मामले के आधार पर निर्गत पत्रांक 2324 दिनांक 10.07.2007 की विवेचना में भी सुस्थापित कानून के अनुसार भी यह कार्यवाही विधि विरुद्ध है।

पृष्ठ सं0-8 के कंडिका (ii) से स्पष्ट है कि न्यायिक कार्यवाही के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि स्वतंत्र विभागीय कार्यवाही नहीं चलाई गई है। सभी न्यायिक कार्यवाही निराधार है, जिसपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक है। इस कंडिका में असत्य एवं मनगढ़ंत तथ्य समाहित किया गया है। प्रपत्र 'क' या पुलिस महानिरीक्षक के पत्रांक 1201 दिनांक 02.03.2016 में अंकित नहीं है कि इनके द्वारा अचल सम्पत्ति का क्रय/विक्रय किया गया है। जाँच प्रतिवेदन, बचाव बयान, द्वितीय कारण पृच्छा में स्पष्ट हो चुका है कि वर्णित सम्पत्ति स्वावलंबी परिजनों की है, जिससे आरोपी पदाधिकारी की कोई संबद्धता नहीं है तथा सम्पत्ति विवरणी में ऐसे सम्पत्ति के अंकित करना विभागीय पत्र एवं सुस्थापित कानून के तहत आवश्यक नहीं है। विभाग द्वारा विधिविरुद्ध अभिकथन किया गया है कि आर्थिक अपराध इकाई मानक के तहत गणना किया गया है तथा उसके आरोप के आधार पर आरोप प्रमाणित करता है। आर्थिक अपराध इकाई के गणना को अर्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत जाँच आयुक्त द्वारा तीन बार असत्य एवं निराधार पाया जा चुका है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण पाकर कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। पृष्ठ सं0-08 के कंडिका (iii) में स्वीकार किया गया है कि परिजनों द्वारा क्रय/विक्रय किया गया। किसी भी जाँच में प्रमाणित नहीं है कि आरोपी का कोई संबद्धता या संज्ञान उक्त क्रय/विक्रय के संबंध में है। जाहिर है कि पत्रांक 21734 दिनांक 15.11.1976 के आलोक में उक्त सूचना विवरणी में दर्ज करना आवश्यक नहीं है। साथ ही प्रतिवेदन से असहमति एवं प्रश्नगत आदेश गलत है।

बिहार आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के प्रावधानों का उल्लंघन तीन बार 08 वर्ष तक जाँच में भी प्रमाणित नहीं किया जा सका। कर्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का आरोप बिना प्रमाणित किए अभिकथित करना अनुचित है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2022 को पारित न्यायादेश में अनुलग्नक 05 पर निर्णय लेते हुए विभागीय कार्यवाही पर निर्णय लेने का निदेश है, लेकिन दिनांक 15.02.2022 के आदेश के आलोक में अभ्यावेदन पर बिन्दुवार एवं स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यवाही पर स्थगन के मद्येनजर विभागीय कार्यवाही में स्वतंत्र आदेश पारित किया गया, जिस पर रोक है। दिनांक 18.05.2021 के बाद न्यायादेश पारित है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया।

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 9999/2020 में दिनांक 15.02.2022 को पारित आदेश से पूर्व ही निर्णय लिया जा चुका था। बिहार लोक सेवा आयोग की भूमिका परामर्शी की है जिसे मानना विभाग की बाध्यता नहीं है। स्मारित कर अतिरिक्त दबाव बनाया गया, जिसके कारण आयोग से सहमति दी गई।

प्रश्नगत संकल्प सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली, 2005, आचार नियमावली, 1976 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311, 14, 16, 19, 20, 21, 300 एवं मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा T.P.Cr. No.-620/19 मान0 उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No. 7549/15 एवं 9999/2020 में निर्गत न्यायादेश के प्रतिकूल है। यह संकल्प 1994 A.R. 853, 1994 Sec(1) S.P.C Naidu Vs jagannath, Roop singh Negi Vs Punjab National Bank 2008, Union of India Vs K.K. Dhawan 1993, AIR 1478 1993 SEC (1) 296, M.V. Bijlani Vs Union of India 2006, Capt. M. Paul Anthony Vs Bharat gold mines Ltd, Kusheshwar Dubey Vs Bharat coking coal Ltd., Jang Bahadur Singh Vs Baijnath Tiwari, State of Rajsthan Vs B.K. Meena (1996) 6SCC417, A.K. Kraipak Vs Union of India, K.R. Deb Vs Collector of Central Excise 1971, AIR 1447, 1971 SCR 375 आदि द्वारा दिए गए व्यवस्था के प्रतिकूल है तथा विधि विरुद्ध एवं नियम विरुद्ध है।

श्री त्रिवेदी से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा प्रतिवेदित आरोपों एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। श्री त्रिवेदी द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में समर्पित स्पष्टीकरण के तथ्यों को ही पुनः उल्लेख किया गया है। श्री त्रिवेदी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त उनके विरुद्ध शास्ति अधिरोपित की गई। श्री त्रिवेदी के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप प्रतिवेदित है। इनके विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधानोपरान्त आरोप-पत्र माननीय विशेष न्यायालय में समर्पित किया गया एवं कांड पर माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत श्री त्रिवेदी के विरुद्ध माननीय प्राधिकृत पदाधिकारी-विशेष न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर के समक्ष अधिहरण वाद दाखिल करने हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना की घोषणा संख्या 11220 तथा 11221 दिनांक 31.12.2007 के आलोक में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। श्री त्रिवेदी द्वारा कई चल अचल सम्पत्ति का क्रय एवं बिक्रय किया गया है, जिसका उल्लेख उनके द्वारा समर्पित सम्पत्ति विवरणी में नहीं किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधानोपरान्त श्री त्रिवेदी के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित किये जाने का आरोप प्रतिवेदित है। बिहार सरकारी आचार नियमावली, 1976 के प्रावधान के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 946 दिनांक 24.01.2011 के आलोक में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को विहित प्रपत्र में चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित किया जाना अनिवार्य है, जिसका उल्लंघन श्री त्रिवेदी द्वारा किया गया है।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री त्रिवेदी के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4820 दिनांक 29.03.2022 द्वारा अधिरोपित (i) संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धि पर रोक एवं (ii) देय प्रोन्नति की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक के लिए प्रोन्नति पर रोक का दंड को पूर्ववत् बरकरार रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अभिराम त्रिवेदी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 964/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, वैशाली-सह-अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4820 दिनांक 29.03.2022 द्वारा अधिरोपित (i) संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धि पर रोक एवं (ii) देय प्रोन्नति की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक के लिए प्रोन्नति पर रोक का दंड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
शिवमहादेव प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 642-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>